डाक पंजीयन सं. आर.जे./जे.पी.सी./मन्थली–08/2010–12 RNI - 65127/94

सहकार समाचार बुलेटिन

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं

वर्ष : 16 अंक : 12 वार्षिक :100 रु एक प्रति : 10 रु अगस्त, 2010

21 लाख किसानों को 5 हजार करोड़ के फसली ऋण के लिए ब्याज अनुदान के 30 करोड़ रुपए जारी

राज्य सरकार अधिकाधिक काश्तकारों को फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की इस वर्ष के बजट में की गई घोषणा की क्रियान्विति के लिए यह राशि ब्याज अनुदान मद में दी है। श्री गहलोत ने बजट में 30 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान देने की घोषणा की थी, जिसमें से 20 करोड़ रुपये की राशि पूर्व में उपलब्ध थी। राज्य सरकार के इस निर्णय से इस वित्तीय वर्ष में 16 लाख की बजाय 21 लाख किसानों को 5 हजार करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण देना संभव हो सकेगा। इससे पहले के वर्ष में राज्य सरकार ने 16 लाख किसानों को 3 हजार 230 करोड़ रुपए के फसली ऋण वितरित किए थे।

बजट घोषणा की क्रियान्विति

5 लाख 50 हजार नए काश्तकार सहकारी ऋण सुविधा से जुड़े

राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ में रेकार्ड 5 लाख 50 हजार नए काश्तकारों को फसली सहकारी ऋण उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने बताया कि यह अब तक के प्रदेश के सहकारी ऋण वितरण के इतिहास में पहला अवसर है जब किसी एक वर्ष में ही 5 लाख से अधिक नए काश्तकारों को सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था से जोड़ा गया है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार खरीफ में अब तक लगभग 2800 करोड़ रुपए से अधिक के फसली सहकारी ऋण दिए गए हैं जो गत वर्ष से करीब 900 करोड़ रुपए अधिक है। उन्होंने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 14 लाख से अधिक काश्तकार सदस्यों को फसली सहकारी कर्जे उपलब्ध कराए जा चुके हैं। खरीफ के लिए 30 अगस्त तक फसली सहकारी ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे।

रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में इस वित्तीय वर्ष में फसली सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था से 5 लाख नए काश्तकारों को जोड़ते हुए खरीफ और रबी में मिलाकर 5 हजार करोड़ रुपए के फसली सहकारी ऋण वितरण की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग ने खरीफ में ही 5 लाख 50 हजार से अधिक काश्तकारों को फसली सहकारी ऋण उपलब्ध कराकर मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की शतप्रतिशत

से भी अधिक क्रियान्विति कर दी है।

श्री शर्मा ने बताया कि इस वर्ष खरीफ में नए काश्तकार सदस्यों को लगभग 900 करोड़ के फसली सहकारी ऋण दिए गए हैं। संभवतः यह पूरे देश में एक वर्ष में ही इतनी बड़ी संख्या में नए सदस्यों को फसली सहकारी कर्जे उपलब्ध कराने का कीर्तिमान होगा।

रजिस्ट्रार श्री शर्मा ने बताया कि सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा, प्रमुख शासन सचिव श्री आर.के. मीणा व रजिस्ट्रार के साथ उच्च स्तरीय बैठक में खरीफ में ही 5 लाख नए काश्तकारों को जोड़ने का निर्णय लिया गया। अप्रेल व मई माह में अभियान चलाकर नए सदस्यों को सहकारी किसान कार्ड वितरण के साथ ही ऋण वितरण पर जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि सहकारी ऋणी सदस्यों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए 31 जुलाई तक खरीफ के लिए ऋण वितरण पर खास बल दिया गया।

श्री शर्मा ने बताया कि सर्वाधिक 1 लाख 54 हजार नए काश्तकारों को जोधपुर संभाग में जोड़ा गया है। इसी तरह से बीकानेर संभाग में 89 हजार 216, जयपुर संभाग में 82 हजार 96, अजमेर संभाग में 74 हजार 513, उदयपुर संभाग में 54 हजार 336, भरतपुर संभाग में 42 हजार 600 एवं कोटा संभाग के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 35 हजार510 नए काश्तकारों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से फसली सहकारी ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, नागौर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक के क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में लक्ष्यानुसार शतप्रतिशत से भी अधिक नए काश्तकार सहकारी ऋण व्यवस्था का लाभ प्राप्त कर पाए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में खरीफ ऋण वितरण की समाप्ति तक सर्वाधिक सदस्यों एवं खरीफ में किसी एक वर्ष में सर्वाधिक फसली सहकारी ऋण वितरण का कीर्तिमान बन जाएगा।

तिलम संघ 3 करोड़ 50 लाख रुपए के परिचालन लाभ में
राज्य सरकार को एक करोड़ रुपए चुकाए

वर्षों से हानि में चल रहे तिलम संघ ने राज्य सरकार को पहली बार एक करोड़ 5 लाख रुपए ऋण के पेटे चुकाए हैं। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने बताया कि वर्ष 2009-10 में तिलम संघ 3 करोड़ 50 लाख रुपए के परिचालन लाभ में रहा है।

रजिस्ट्रार श्री शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने तिलम संघ को दिए राहत पैकेज के तहत तिलम संघ के ऋण के पेटे ब्याज को फ्रीज करते हुए चुकाए जाने वाले राशि की दोगुनी राशि ब्याज के रूप में माफ करने का निर्णय किया है। पैकेज के अनुसार तिलम संघ परिचालन लाभ में से पहले वर्ष 30 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 40 प्रतिशत, तीसरे वर्ष 50 प्रतिशत व इसके बाद 60 प्रतिशत तक की राशि ऋण के रूप में चुकाएंगे और चुकाई गई राशि की दोगुनी राशि ब्याज में से माफ की जाएगी।

श्री शर्मा ने बताया कि प्रबन्धकीय दक्षता से संचालन पर जोर देते हुए तिलम संघ के कार्यों में विविधिकरण किया गया है। तिलम संघ द्वारा अब सोयाबीन, मूंगफली और सरसों तेल एक लीटर से 15 किलोग्राम तक पैकिंग में विक्रय के साथ ही उन्नत प्रमाणिक बीजों का प्रसंस्करण करते हुए काश्तकारों को बीज वितरण, तिलम फ्राइपेन श्रृंखला का संचालन, तिलम पोहा की बिक्री जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं।

श्री शर्मा ने भावी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में प्रमाणिक बीजों की कमी को देखते हुए तिलम संघ इस वर्ष से प्रदेश में मूंग, मोठ और ग्वार के प्रमाणिक बीजों का प्रसंस्करण भी शुरु करेगा। इससे पहले तिलम संघ के कोटा प्लान्ट में गेहूं, चना, सरसों और सोयाबीन के प्रमाणिक बीज तैयार कर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। तिलम संघ द्वारा बीज प्रसंस्करण के लिए कोटा, फतेहनगर, श्रीगंगानगर में एक-एक बीज संस्करण इकाई और लगाई जा चुकी हैं।

श्री शर्मा ने बताया कि तिलम संघ की बीज प्रोसेसिंग इकाई में 61 हजार 300 क्विंटल प्रमाणिक बीज तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसमें 33 हजार क्विंटल सोयाबीन, 4 हजार 400 क्विंटल सरसों, 22 हजार 400 क्विंटल गेहूं, 300-300 क्विंटल चना, मूंग और मोठ तथा 600 क्विंटल ग्वार के प्रसंस्करित बीज तैयार किए जाएंगे। गत वर्ष तिलम संघ ने 53 हजार 765 क्विंटल सोयाबीन, सरसों और गेहूं के प्रमाणिक बीज का उत्पादन किया था।

तिलम संघ की प्रबंध संचालक श्रीमती शशि मधोक ने बताया कि वर्ष 2009-10 के दौरान 13 हजार 575 टन सोयाबीन, 7 हजार 378 टन सरसों और 3 हजार 413 टन से अधिक मूंगफली की खरीद की गई। इस वर्ष 14 हजार 500 टन सोयाबीन, 7 हजार 100 टन सरसों और 3 हजार 500 टन मूंगफली की खरीद का कार्यक्रम बनाया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम के लिए तिलम संघ ने 17 हजार 900 टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद की है।

समग्र सहकारी विकास परियोजना की समीक्षा बैठक
13 जिलों की सहकारी संस्थाओं को मिलेंगे 213 करोड़ रुपए - सहकारिता रजिस्ट्रार

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने समग्र सहकारी विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सहकारी संस्थाओं को वित्तीय व अन्य संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें सक्षम सहकारी समिति के रूप में विकसित करे, ताकि जिले के काश्तकारों सहित आमनागरिकों को बेहतर सहकारी सुविधाएं दी जा सके। उन्होंने कहा कि परियोजना की क्रियान्विति में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

श्री शर्मा ने सहकार भवन में एनसीडीसी के वित्तीय सहयोग से संचालित समग्र सहकारी विकास परियोजना अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 13 जिलों में संचालित समग्र सहकारी विकास परियोजना के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध राशि के वित्तीय प्रस्ताव एक माह में तैयार कर सहकारी संस्थाओं को राशि उपलब्ध कराए।

रजिस्ट्रार ने बताया कि राज्य के 13 जिलों में 213 करोड़ 48 लाख रुपए की आईसीडीपी परियोजना का संचालन किया जा रहा है। पांच साल की इस योजना में 78 करोड़ 12 लाख रुपए की परियोजना भरतपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर, कोटा व बीकानेर जिलों में इसी वर्ष से शुरू की गई है, वहीं 135 करोड़ 35 लाख रुपए की इस परियोजना का बारां, दौसा व हनुमानगढ़ में अंतिम वर्ष एवं अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, जैसलमेर व झुंझुनू में चौथा वर्ष चल रहा है।

श्री शर्मा ने बताया कि समग्र सहकारी विकास परियोजना का संचालन जिलों की सहकारी संस्थाओं को आधारभूत सुविधाएं, हिस्सा राशि, मार्जिन मनी, ऋण, कम्प्यूटरीकरण, गोदाम-दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर, जिले में सहकारिता के प्रचार-प्रसार व अनुदान के रूप में किया जा रहा है। परियोजना के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखा जावे। परियोजना के तहत राशि की उपलब्धता से संस्थाओं में वित्तीय संसाधन बढ़ सकेंगे और इससे सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों व नागरिकों को बेहतर सेवाएं दे सकेंगी।

रजिस्ट्रार ने बताया कि परियोजना के तहत दिए जाने वाले फर्नीचर-फीक्चर्स, कम्प्यूटर्स, सुपरमार्केट व गोदामों के निर्माण और तिजोरियों आदि कार्यों में गुणवत्ता रखी जावे। समितियों की आवश्यकता को देख कर ही राशि दी जाए, ताकि संस्थाओं पर अनावश्यक वित्तीय भार न पड़े।

एमओ आईसीडीपी श्री रामजी लाल सोनी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 13 जिलों को अब तक 138 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। एएमओ श्री आर.के. सक्सैना ने जिलेवार प्रगति की जानकारी दी। बैठक में सभी 13 जिलों के परियोजना अधिकारी उपस्थित थे।

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ राजफैड को कृभको की ओर से 33 लाख 78 हजार रुपए का लाभांश का चैक प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा एवं प्रबंध संचालक राजफैड श्री विकास एस. भाले को कृभको के महाप्रबंधक श्री जी.एस. कटारिया व मुख्य राज्य विपणन प्रबंधक श्री एस.पी.सिंह ने भेंट किया।

इफको सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला शुरू

खेत सीधे जुड़ेंगे प्रयोगशाला से -प्रमुख शासन सचिव सहकारिता

सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आर.के. मीणा ने कहा कि प्रदेश के खेतों की जमीन के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए सहकारिता के माध्यम से अब किसान के खेत को सीधे प्रयोगशाला से जोड़ा जाएगा। श्री मीणा ने राजफैड में इफको की सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वाहन को हरी झण्डी दिखाकर जयपुर से रवाना किया। इस अवसर पर राजफैड के प्रबंध संचालक श्री विकास एस. भाले भी उपस्थित थे।

श्री मीणा ने बताया कि इफको द्वारा संचालित इस सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा प्रतिदिन 50 नमूनों का गॉवों में ही निःशुल्क परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण के बाद काश्तकारों को मिट्टी के अनुरूप ली जाने वाली फसलों के लिए आवश्यक खाद व उसके उपयोग की जानकारी दी जाएगी।

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री मीणा ने बताया कि इस प्रयोगशाला से काश्तकारों को खेत में निःशुल्क मिट्टी परीक्षण की सुविधा प्राप्त होने के साथ ही किसानों को उनके खेत में किस फसल की बुआई करनी चाहिए, किस-फसल के लिए कितने उर्वरकों की आवश्यकता है और किस प्रकार के कीटनाशक उपयोगी हो सकेंगे, की जानकारी प्राप्त होगी।

श्री मीणा ने बताया कि इफको की ओर से संचालित इस मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में प्रतिदिन 50 नमूने लेकर ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशतता, उपलब्ध फॉसफोरस, पोटाश का पता लगाया जा सकेगा व मृदा पीएच, क्षारीयता आदि की जॉच हो सकेगी। इससे मृदा सुधार कार्य में सहायता मिलने के साथ ही किसानों को कम लागत में बेहतर कृषि पैदावार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। जॉच परीक्षण की रिपोर्ट उसी दिन गाँव में ही कृषक सभा का आयोजन कर दी जाएगी। इस सभा में विशेषज्ञों द्वारा कृषि तकनीक की भी जानकारी दी जाएगी।

इफको के मण्डल प्रबन्धक डॉ. आर.आर. राण्डड ने बताया कि इफको द्वारा खेती को आसान बनाने के लिए काश्तकारों तक आधुनिकतम तकनीक भी पहुंचाई जा रही है।

इफको के राज्य विपणन प्रबंधक श्री एस.पी. सिंह ने बताया कि राज्य में इफको के पांच क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं। इफको द्वारा डीएपी, एनपीके और यूरिया के वितरण के साथ ही कृषि विकास की सहगतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। श्री सिंह ने बताया कि इफको ने राज्य में 29 से अधिक गॉवों को गोद लेकर उनके विकास में योगदान दे रही है। इस अवसर पर इफको, राजफैड व सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

सहकार इफको-टोकियो सुरक्षा बीमा योजना में एक लाख का चैक

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा व रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने राजस्थान सहकार इफको-टोकियो सुरक्षा बीमा योजना में बीमित निवारु मॉडल की संचालिका श्रीमती भगवती देवी के असामयिक निधन होने पर उनके परिजनों को बीमा दावे का एक लाख रुपए का चैक दिया। श्रीमती भगवती देवी का ट्रेड सुविधा पॉलिसी के तहत बीमा किया गया था।

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा ने बताया कि निवारु मॉडल के नाम से हस्तशिल्प की पहचान बनाने वाली महिला का पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा इफको के सहयोग से संचालित इफको-टोकियो सुरक्षा बीमा योजना में बीमित होने से महिला के परिजनों को एक लाख रुपए दिए गए। उन्होंने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्यों, कार्मिकों सहित समिति के ऋणी सदस्यों को बीमा सुविधा का लाभ दिया जा रहा है।

श्री मीणा ने कहा कि राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय- विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से बीमा सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीमा की जिम्मेदारी संबंधित संस्थाओं को देने से संस्थाएं एजेन्ट के रुप में काम करते हुए गाँव में ही बीमा सेवाएं उपलब्ध करा रही है।

रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने बताया कि सामाजिक दायित्व की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए सहकारियों में बीमा सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। योजना के तहत साधारण बीमा के साथ ही चोरी-चकोरी, दुर्घटना, मौसमी बीमा, बारिश बीमा आदि का लाभ दिया जा रहा है।

राजस्थान इफको-टोकियो सुरक्षा बीमा योजना के सलाहकार श्री हीरालाल ने बताया कि अब तक राज्य में 5 सहकारी समितियों के कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक-एक लाख रुपए की बीमा दावे के चैक दिए जा चुके हैं। संकट हरण बीमा योजना में किसानों को खाद की खरीद पर स्वतः बिना किसी प्रीमियम के बीमित कर लाभान्वित किया जा रहा है।

जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध संचालक श्री विष्णु वर्मा ने बताया कि बैंक की ग्राम सेवा सहकारी समितियों, इनके कार्मिकों आदि का बीमा कराया हुआ है।

सहकारिता विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

अभियान चलाकर फसली सहकारी ऋण उपलब्ध कराएं

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा ने केन्द्रीय सहकारी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के नए पुराने काश्तकार सदस्यों को अभियान चलाकर खरीफ सहकारी ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। फसली सहकारी ऋण वितरण के लिए पर्याप्त मात्रा में राशि उपलब्ध है।

श्री मीणा रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा के साथ सहकारी बैंकों के प्रबंध संचालकों, सचिवों, इकाई अधिकारियों के कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुराने सदस्यों को 15 जुलाई तक वितरित खरीफ फसली सहकारी ऋणों पर ही मौसम बीमा सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकेगा। आवश्यकता होने पर ऋण शिविर आयोजित कर फसली सहकारी ऋण वितरित किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बीमा योजना की राशि प्राप्त हो गई है, संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंकों को यह राशि काश्तकारों के लिए जारी कर दी गई है।

श्री मीणा ने कहा कि 5 लाख नए काश्तकारों को 31 जुलाई तक सहकारी फसली ऋण सुविधा से जोड़ा जाना है। इस वर्ष खरीफ में 4200 करोड़ के फसली सहकारी कर्जे वितरित होने हैं। फसली सहकारी ऋण वितरण में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से वितरित फसली सहकारी ऋणों पर भी दो प्रतिशत ब्याज सबवेंसन का लाभ देय हैं। उन्होंने प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण वितरण में विविधिकरण लाने की आवश्यकता जताई।

रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने आदान अनुदान की राशि संबंधित किसानों को उपलब्ध कराने, खाते खोलकर संबंधित किसान को पासबुक जारी कर तुरन्त फेक्स से सूचित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऋण राहत योजना के तहत उपलब्ध सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं करने वाले ऋणियों से बकाया वसूली के लिए सख्त कदम उठाते हुए किसी तरह की रियायत नहीं बरतने के निर्देश दिए। पर्याप्त राहत देने के प्रयास के बाद भी ऋण नहीं चुकाने का सीधा अर्थ है कि शेष बचे ऋणी जानबूझकर सहकारी बैंकों का पैसा नहीं चुकाना चाहते हैं।

श्री शर्मा ने कहा कि रिद्धी-सिद्धी व खुशहाली योजना में जिन समितियों को लाइसेंस प्राप्त हो गया है, उन समितियों के व्यवस्थापकीय अनुदान एवं कार्यशील पूंजी अविलंब जारी की जावे। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में समान लेखा पद्धति को प्राथमिकता से लागू करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि नाबार्ड को सूचनाएं नई पद्धति से ही देनी होगी।

राजफैड के प्रबंध संचालक श्री विकास एस. भाले ने बताया कि सहकारी समिति स्तर पर 33651 क्विंटल बीज उपलब्ध कराये जा चुके हैं। राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध संचालक श्री आर.सी.एस. जोधा ने बताया कि 4 लाख 76 हजार नए काश्तकारों को सहकारी ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। राज्य भूमि विकास बैंक के प्रबंध संचालक श्री विजय जोशी ने दीर्घकालीन ऋणों की वसूली पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उपभोक्ता संघ के प्रबंध संचालक श्री आर.एस. जाखड़ ने लेवी चीनी का तत्काल उठाव कर 15 से 20 तक आयोजित पखवाड़े में वितरण सुनिश्चित कराने को कहा। वीसी में उपसचिव सहकारिता श्री महेश गुप्ता, पीडीएम श्री महेन्द्र सिंह जावला, संयुक्त रजिस्ट्रार बैंकिंग श्री हनुमान सिंह, श्री रामजी लाल सोनी, मुख्य अंकेक्षक श्री आई.एल. राव, मुख्यलेखाधिकारी श्री अरविन्द मिश्रा उपस्थित थे।

उच्च शिक्षा के लिए ऋण सस्ता, अन्य ऋणों की ब्याज दरें भी घटाई

APEX BANK

उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए अब राजस्थान राज्य सहकारी बैंक **अपेक्स बैंक** से दो प्रतिशत कम ब्याज दर पर युवाओं को ऋण प्राप्त हो सकेगा।

सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आर.के. मीणा ने बताया कि अपेक्स बैंक ने शिक्षा ऋण सहित गैर कृषि ऋणों की ब्याज दरों में आधा प्रतिशत तक की कमी की है। अपेक्स बैंक की ब्याज दरों में कमी का निर्णय आमनागरिकों को सस्ती दर पर बेहतर ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। श्री मीणा ने बताया कि सहकारी बैंकों के माध्यम से फसली सहकारी कर्जे पहले से ही 7 प्रतिशत की ब्याज दर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और नियमित ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को दो प्रतिशत की छूट के साथ पांच प्रतिशत की ब्याज दर पर फसली सहकारी कर्जे उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

श्री मीणा ने बताया कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों व विपणन सहकारी समितियों को फर्टीलाइजर व्यवसाय के लिए भी अब दो प्रतिशत की कमी के साथ 9 प्रतिशत पर ही साख सीमा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक श्री आर.सी.एस. जोधा ने बताया कि परिवर्तित ब्याज दरों के अनुसार अब एनएससी के विरुद्ध 11 प्रतिशत, व्यक्तिगत ऋण 13 प्रतिशत, टर्म लोन 12.50 प्रतिशत, वाहन ऋण पहले वर्ष 8 प्रतिशत, बाद में 10 प्रतिशत एवं व्यावसायिक वाहनों पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाएगा। आवास ऋणों की ब्याज दर को कम करते हुए फिक्स दर साढ़े नौ प्रतिशत एवं फ्लोटिंग दर पहले वर्ष के लिए साढ़े 8 प्रतिशत की गई है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए 12 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण दिया जा सकेगा। आईआईएम, आईआईटी, मेडिकल अध्ययन के लिए 10 प्रतिशत एवं अन्य शिक्षा ऋण 11.50 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकेगा।

सहकारिता मंत्री ने चुरू केन्द्रीय सहकारी बैंक परिसर में किया वृक्षारोपण

चूरू जिला अरबन को-ऑपरेटिव बैंक सार्दुलपुर के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने चूरू जिला मुख्यालय पर अपने अल्पकालिक प्रवास के दौरान चूरू केन्द्रीय सहकारी बैंक परिसर में वृक्षारोपण कर 'हरित राजस्थान अभियान' का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया।

हरित राजस्थान अभियान शुभारंभ समारोह के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत वृक्षारोपण समय की मांग है तथा हमें राज्य सरकार के हरित राजस्थान अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सामुहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने अपने उद्‌बोधन में बैंक द्वारा स्व निर्मित भवन व बैंक परिसर में बने एक लाख लीटर क्षमता वाले पानी का टांका, जिसमें बैंक भवन की छत के पानी का सदुपयोग कर सार्वजनिक प्याऊ का संचालन करने के लोककल्याणकारी कार्य के लिए समस्त बैंक परिवार को साधुवाद दिया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। सहकारिता में आम आदमी की सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ ही सहकारिता विकास की गति में काफी बढ़ोतरी की जा रही है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बैंक के अध्यक्ष श्री पूर्णराम गिल ने अपने उद्‌बोधन में सहकारिता मंत्री के बैंक परिसर में पधारने पर आभार व्यक्त किया। बैंक के प्रबंध निदेशक श्री नेतराम यादव ने स्वागत करते हुए बैंक द्वारा संचालित विभिन्न अभिनव सहकारी ऋण योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए बैंक की प्रगति से अवगत करवाया। समारोह में हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री संदीप डूडी व भूमि विकास बैंक चूरू के अध्यक्ष श्री मूलाराम कस्वां ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

इससे पूर्व सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने बैंक सभा भवन में जिला कलक्टर श्री के.के. पाठक से बैंक गतिविधियों की चर्चा की तो जिला कलेक्टर ने जानकारी दी कि बैंक द्वारा नरेगा संबंधित मिनी बैंकों से भुगतान का प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है। बैठक में संयुक्त रजिस्ट्रार श्री युसुफ खान, भूमि विकास बैंक के सचिव श्री एन.के. मोर्य, सहायक रजिस्ट्रार श्री रामावतार चौधरी, बैंक के अधिशाषी अधिकारी श्री रामावतार स्वामी सहित अन्य विभागीय अधिकारियों की संक्षिप्त बैठक में नरेगा, कृषि आदान अनुदान,स्वयं सहायता समूह, नए सदस्य बनाए जाने पर चर्चा की गई।

प्रदेश मे 68 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन

जोधपुर-टोंक में 25 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां

राज्य सरकार ने प्रदेश के जोधपुर- टोंक जिले में 25 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति जारी की है। नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समितियों को स्थानीय ग्राम पंचायतों द्वारा प्रथम पांच वर्ष के लिए भवन तथा गोदाम निर्माण के लिए निःशुल्क भूखण्ड उपलब्ध करवाया जाएगा।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने बताया कि इसी वर्ष मई माह में बाड़मेर, सीकर व जोधपुर जिले में 43 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। लगभग 33 साल बाद इस साल प्रदेश में अब तक 68 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

जिला कलक्टर की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफारिश पर टोंक पंचायत समिति में 13, निवाई में 5 तथा देवली, टोडारायसिंह तथा मालपुरा में एक-एक नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति जारी करते हुए जिले के सहायक/उप रजिस्ट्रार को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर पंजीयन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह से जोधपुर जिले में ओसियां पंचायत समिति के बेगू, बाप पंचायत समिति के जोड, राणेरी एवं ननेउ ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की है। अन्य जिलों में भी नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गतवर्ष नवम्बर-दिसम्बर में राज्य मंत्रीमण्डल के चिंतन शिविर में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन में आ रही बाधाओं पर विस्तार से विचार विमर्श के बाद हिस्सा राशि 15 लाख से घटाकर 7 लाख रुपए करने का निर्णय किया, जिससे नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन में आ रही बाधा दूर होने से समितियों के गठन का सिलसिला शुरु हो गया है।

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने काश्तकरों को निकटतम स्थान से फसली सहकारी ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की आवश्यकता प्रतिपादित की थी।

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा व रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठकों में जिलाधिकारियों को नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। राज्य में अंतिम बार 1977 में ग्राम सेवा सहकारी समितियों/लेम्पस का पुनर्गठन हुआ था।

अक्टूबर, 08 में मंत्रीमण्डलीय आज्ञा से रोक हटाने के बावजूद हिस्सा राशि का प्रावधान व्यावहारिक नहीं होने से समितियों का गठन नहीं हो पा रहा था। नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन/पुनर्गठन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में अध्यक्ष व प्रबंध संचालक केन्द्रीय सहकारी बैंक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद व उप/सहायक रजिस्ट्रार की समिति की सफिारिश पर किया जा रहा है। समितियों का गठन या पुनर्गठन पांच सौ काश्तकार मिलकर 7 लाख की हिस्सा राशि से कर सकते हैं।

टोंक पंचायत समिति की कुरेड़ा, हरचन्देडा, डारडाहिन्द, बरोनी, दाखिया, काबरा, लोहरवाड़ा, बनवाड़ा, कठमाना, बगवाड़ा, चौगाई, काशीपुरा तथा नाथड़ी ग्राम पंचायत में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन होगा। इसी प्रकार निवाई पंचायत समिति की ललवाड़ी, बड़ा गांव, चतुर्भुजपुरा, राहोली, हिंगोनियां ग्राम पंचायत में तथा देवली पंचायत समिति की रामसागर, टोडारायसिंह की मूडियाकलां एवं मालपुरा ग्राम पंचायत में भी नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सीकर में महिला सहकारी सुपर मार्केट का लोकार्पण

सहकारी क्षेत्र मे निर्मित महिला सहकारी सुपर मार्केट का रविवार को यहां समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। समारोह के अध्यक्षता पूर्व मंत्री चौधरी श्री नारायण सिंह ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केन्द्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री महादेव सिंह खण्डेला ने कहा कि इस सुपर मार्केट से आम आदमी लाभान्वित होकर न केवल रोजमर्रा के सामान की जरुरत पूरी कर सकेंगे बल्कि लोग, खास कर जिले की महिलाएं सहकारिता आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित भी हो सकेंगी। उन्होंने सनातन काल से देश व समाज में स्थापित नारी के महत्व को पुस्तकीय उदाहरण देकर रेखांकित किया।

समारोह के विशिष्ट अतिथि एवं राज्य के उद्योग व आबकारी मंत्री श्री राजेन्द्र पारीक ने इस मार्केट को सीकरवासियों के लिए एक अनूठी सौगात बताते हुए जिले भर में ऐसे बाजार खोलने की आवश्यकता बतलाई। उन्होंने कहा कि आज सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने के लिए स्व. राजीव गांधी का सपना साकार हो रहा है, जिससे देश के विकास को नई दिशा प्राप्त होगी। उद्योग मंत्री ने इस सुपर मार्केट की हर कीमत पर विश्वसनीयता स्थापित कर इसे आदर्श मार्केट का रूप देने की सलाह दी। उन्होंने महिलाओं द्वारा संचालित इस सुपर मार्केट को एक क्रांतिकारी उपलब्धि बताया।

सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप सहकारी क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने के लिए यह सुपर मार्केट खोला गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सहकारी बैंकों के माध्यम से गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष पांच लाख नए किसानों को ऋण वितरित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य की 40 तहसीलों में 80 ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाने की स्वीकृति दी गई है।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में पूर्व मंत्री श्री नारायण सिंह ने सीकर में प्रदेश का प्रथम महिला सुपर मार्केट खोलने पर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार का आभार जताया। उन्होंने इस सुपर मार्केट का संचालन पूर्ण सेवा-भाव, ईमानदारी से करने की जरुरत बताई, ताकि प्रतिस्पर्धा के दौर में इसकी विश्वसनीयता कायम हो सके। उन्होंने आशा प्रकट की कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे सुपर मार्केट खोले जाएंगे। जिला प्रमुख श्रीमती रीटा सिंह, लक्ष्मणगढ़ के विधायक श्री गोविन्द सिंह डोटासर, सीकर नगर परिषद की सभापति सलमा शेख तथा जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री खेमचन्द महला ने भी विचार व्यक्त किए। प्रारम्भ में सीकर महिला उपभेक्ता सहकारी भण्डार की अध्यक्षा सुधा महला ने स्वागत भाषण में बताया कि इस सुपर मार्केट में बाजार मूल्य से एक प्रतिशत कम कीमत पर गुणवत्तायुक्त सामान उपभोक्ताओं को उपलब्ध होगा। उन्होंने एस.के. अस्पताल में दवाइयों का पृथक महिला उपभोक्ता भण्डार खोलने की भी मांग रखी। समारोह में अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। समारोह के बाद सभी अतिथियों ने सुपर मार्केट का अवलोकन किया। मंच संचालन राकेश लाटा व रेखा शर्मा ने संयुक्त रूप से किया।

सहकारी ऋण अब और आसान, बिचौलियों से मिलेगी मुक्ति

राज्य में सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था को सरल बनाते हुए सहकारी बैंकों के ऋणियों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाई गई है। सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आर.के. मीणा ने बताया कि अब राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा निजी कोष से दिए जाने वाले ऋण नकद दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब तक ऋणी सदस्य को डीलर की इनवॉयस के आधार पर डीलर के नाम चैक काटकर ऋण दिया जाता था, जिससे ऋणी सदस्य को डीलर की मांग के अनुसार सामान क्रय करना पड़ता था।

गौरतलब है कि सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने पिछले दिनों प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा एवं रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा के साथ उच्च स्तरीय बैठक में सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था को आसान बनाने और इस व्यवस्था से डीलर प्रथा को हटाने की आवश्यकता प्रतिपादित की थी। सहकारिता मंत्री श्री मीणा की पहल पर पिछले दिनों केन्द्रीय सहकारी बैंकों से ट्रेक्टर के लिए काश्तकारोंके लिए नकद में ऋण वितरण व्यवस्था शुरु की जा चुकी है। अब फसली सहकारी ऋण भी अब मिनी बैंक से ही मिलने लगे हैं।

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा ने बताया कि प्रदेश के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक अब ट्रेक्टर, ट्रॉली, थ्रेसर एवं अन्य कृषि उपकरणों सहित लघु सिंचाई के लिए सबमर्सिबल पम्प सेट **ई.पी.एस/डी.पी.एस.**, स्प्रिंकलर सिस्टम, पाइपलाईन **एल.एफ.सी.**, ट्यूबवैल, बोरवैल इत्यादि उद्देश्यों के लिए काश्तकारों को सीधे नकद ऋण वितरण कर सकेंगे।

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा ने बताया कि काश्तकारों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सहकारी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि बैंकों द्वारा स्वयं के कोषों से दिए जाने वाले ऋण का भुगतान अब सीधे फर्म अथवा विक्रेता को न करके काश्तकारों को ही किया जाएगा। इससे काश्तकार बारगेनिंग कर ट्यूबवैल और बोरवैल के कार्य न्यूनतम दर से करवा सकेंगे। बाजार से कम से कम मूल्य पर मनपसंद ब्राण्ड के ट्रेक्टर, ट्रॉली, थ्रेसर एवं अन्य कृषि उपकरणों सहित लघु सिंचाई के लिए सबमर्सिबल पम्प सेट ई.पी.एस/डी.पी.एस., स्प्रिंकलर सिस्टम, पाइपलाईन एल.एफ.सी. आदि क्रय कर सकेंगे।

रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने बताया कि नाबार्ड की ऋण नीति के अनुसार अब तक खरीद के लिए ऋण राशि का भुगतान सीधे फर्म एवं विक्रेता को ही किया जाता था, किन्तु क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार यह अनुभव किया गया कि नकद राशि से ट्रेक्टर आदि क्रय करने वाले लाभार्थियों को बैंक ऋण से क्रय करने वालों की अपेक्षा विक्रेताओं द्वारा अधिक छूट दी जाती है। इस योजना के लागू होने से काश्तकारों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा।

श्री शर्मा ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने वाले काश्तकारों को बैंक में बचत खाता खोलना जरुरी है। काश्तकार को अपने ऋण प्रार्थना पत्र के साथ बचत खाते की पास बुक के पहले पृष्ठ की फोटो कॉपी एवं बचत खाता संख्या अंकित करनी होगी तथा संयुक्त ऋण के मामलों में ऋणियों को संयुक्त खाते खुलवाने होंगे। उन्होंने बताया कि ऋण प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तावित उद्देश्य का उल्लेख किया जाना जरूरी है, यथा- ट्रेक्टर के मामले में मॉडल एवं हॉर्सपावर तथा लघु सिंचाई के प्रयोजन यथा सबमर्सिबल पम्प सेट **ई**.पी.एस/डी.पी.एस., स्प्रिंकलरसिस्टम, पाइपलाईन एल.एफ.सी., ट्यूबवैल, बोरवैल आदि की प्रस्तावित ऋण राशि भी उल्लेखित होनी चाहिए।

अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री आर.सी.एस. जोधा ने बताया कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऋण की स्वीकृति किसी भी स्थिति में कम्पनी द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य अथवा दी गई छूट के बाद किए गए विक्रय मूल्य से अधिक नहीं होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र अस्वीकृत होने की सूचना सात दिवस के अन्दर अण्डर यूपीसी डाक द्वारा भिजवाई जाएगी तथा स्वीकृत ऋण राशि का भुगतान रेखांकित चैक अथवा पे-आर्डर द्वारा सीधे ऋणी अथवा संयुक्त ऋणियों के खाते में जमा कराया जाएगा।

टफ परियोजना के क्रियान्वयन से स्पिनफैड कताई मिलों की उत्पादकता व लाभदायकता में बढ़ोतरी-सहकारिता मंत्री

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि स्पिनफैड की तीनों कताई मिलों में टफ परियोजना क्रियान्वयन के राज्य मंत्रीमण्डल के निर्णय के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना के योजनावद्ध क्रियान्वयन और राज्य सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय मोनेटरिंग कमेटी के नियमित समीक्षा से स्पिनफैड की कताई मिलों में उत्पादकता एवं लाभदायकता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है।

सहकारिता मंत्री श्री मीणा ने यह जानकारी उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र पारीक के साथ मोनेटरिंग कमेटी की उच्च स्तरीय बैठक में दी। बैठक में प्रमुख शासन सचिव सहकारिता सचिव श्री आर.के. मीणा, रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा, सीएमडी स्पिनफैड सुश्री गुरजोत कोर व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। श्री मीणा ने बताया कि अक्टूबर, 09 में राज्य सरकार ने मंत्रीमण्डल के निर्णय से स्पिनफैड की इकाईयों के आधुनिकीकरण और पुनर्वास की टफ परियोजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया था। परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी का परिणाम यह रहा कि नवम्बर, 09 से ही गुलाबपुरा की कताई मिल लगातार नकद लाभ में काम करने लगी है। गंगापुर व हनुमानगढ़ मिल भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है।

सहकारिता मंत्री श्री मीणा ने स्पिनफैड की तीनों कताई मिलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता प्रतिपादित की, ताकि मिलों के कर्मचारी प्रतिस्पर्धा में काम करते हुए अपनी इकाइयों में उत्पादकता व लाभदायकता बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि गुलाबपुरा कताई मिल के आधुनिकीकरण का कार्य इस वर्ष दिसम्बर तक पूरा हो जाएगा। मिल कुछ मशीनों के चालू होने से पिछले आठ माह से लगातार नकद लाभ में काम करने लगी है। गंगापुर में भी आधुनिकीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है और मार्च, 11 तक पूरा हो जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अगस्त में स्पीडफ्रेम के आने व दिसम्बर में रिंग फ्रेम स्थापित होने के साथ ही मिल की उत्पादकता व लाभदायकता बढ़ जाएगी। इसी तरह से हनुमानगढ़ कताई मिल का आधुनिकीकरण का कार्य भी जारी है और इसे पूरा होने में समय लगेगा। हनुमानगढ़ मिल भी गत आठ में से छह माहों में नकद लाभ में रही है।

उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र पारीक ने टफ परियोजना के क्रियान्वयन को सकारात्मक बताते हुए सुझाव दिया कि तीनों कताई मिलों में विशेषज्ञ अधिकारियों की सेवाएं ली जानी चाहिए। उन्होंने मिलों के लिए कपास सीजन में कम से कम छह माह की कपास एक साथ खरीदने पर जोर देते हुए कहा कि इससे मिलों को सस्ती दर पर कपास मिल सकेगी और उसका सीधा प्रभाव कॉटन यार्न रेसियो पर पड़ने से मिलों की लाभदायकता बढ़ेगी। उन्होंने मिलों के कर्मचारियों के लिए उत्पादकता के साथ ही प्रोत्साहन योजना भी शुरु करने का सुझाव दिया।

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री आर.के. मीणा एवं श्री मुकेश शर्मा ने कहा कि स्पिनफैड इकाइयों की इकाईवार उत्पादकता, लाभदायकता व एकाउन्टिंग व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने बताया कि लगभग बंद कताई मिलों को नया जीवनदान मिला है। उन्होंने कर्मचारियों को प्रशिक्षण-प्रोत्साहन की आवश्यकता जताई।

स्पिनफैड की सीएमडी सुश्री गुरजोत कोर ने कताई मिलों की टफ परियोजना की क्रियान्विति, उत्पादकता, लाभदायकता की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में उपसचिव सहकारिता श्री महेश गुप्ता भी मौजूद थे।

काश्तकारों ने चुकाए 80 फीसदी फसली सहकारी कर्जे

राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में लगभग 80 फीसदी फसली सहकारी कर्जो की वसूली प्रदेशवासियों की फसली सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था के प्रति विश्वास का परिचायक है। गत वर्ष 75 फीसदी फसली सहकारी कर्जों की वसूली हुई थी। अंतिम आंकड़े आने तक यह वसूली गत वर्ष से पांच प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना है।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री मुकेश शर्मा ने बताया कि राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 5 हजार 255 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के काश्तकार सदस्यों को फसली सहकारी ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। सहकारी बैंकों से प्राप्त आरंभिक सुचनाओं के अनुसार 3 हजार 550 करोड़ रुपए की कन्वर्जन सहित वसूली हुई है। 2 हजार 600 करोड़ रुपए की नकद वसूली रही है। राज्य के बूंदी, बाड़मेर, हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक फसली सहकारी कर्जों की वसूली में पहले तीन स्थानों पर रहे हैं। 29 में से 14 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लगभग 80 फीसदी ऋणी काश्तकारों ने फसली सहकारी कर्जों का चुकारा किया है। फसली सहकारी ऋणों की वसूली के अंतिम आंकड़े आना बकाया है।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अवधिपार फसली सहकारी कर्जों की वसूली भी संतोषजनक रही हैं। लगभग 79.34 फीसदी अवधिपार फसली सहकारी कर्जों की वसूली रही है। सहकारी बैंकों में राज्य की 27 जिलों में अकाल के बावजूद 58 प्रतिशत फसली सहकारी ऋणों की नकद वसूली हुई है, जबकि केवल 21 प्रतिशत कर्जों को परिवर्तित किया गया है। प्रदेश के अधिकांश काश्तकार फसली सहकारी ऋणों को समय पर चुकाने में विश्वास रखते हैं।

फसली सहकारी कर्जों की 88 फीसदी नकद वसूली कर झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक अव्वल रहा है। बिना कन्वर्जन के श्री गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक में 80, दौसा में 77 , हनुमानगढ़ में 73, कोटा में 79, झुन्झुनू में 73 प्रतिशत से अधिक फसली सहकारी ऋणों की वसूली हुई है। कन्वर्जन सहित वसूली में बूंदी केन्द्रीय सहकारी बैंक की 92.63, बाड़मेर की 92.29 एवं हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक में 91.45 फीसदी से अधिक वसूली रही है। राज्य में सबसे कम वसूली भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक में 46 फीसदी रही है।

ब्यावर में वातानुकूलित सहकार सुपर मार्केट प्रारंभ

बी.एन.के. सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार ब्यावर ने सहकार सुपर मार्केट प्रारंभ कर दिया है। सहकार सुपर मार्केट में लगभग 1500 एसकेयू उपलब्ध है, उपभोक्ताओं की सुविधाओं का पूर्ण ध्यान रखते हुए सुपर मार्केट को पूर्णतया वातानुकूलित एवं कम्प्यूटराईज किया गया है। सुपर मार्केट में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की ब्रॉण्डेड कम्पनियों की उपभोक्ता सामग्री बाजार से सस्ती एवं शुद्ध उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। औसतन प्रतिदिन 150 उपभोक्ताओं द्वारा पूर्ण रुचि लेते हुए सुपर मार्केट में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाया जा रहा है।

ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र बनेगी ग्राम सेवा सहकारी समितियां

संचालक मण्डल की भी तय होगी जबावदेही – सहकारिता मंत्री

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से गाँव, गरीब, दस्तकारों, महिलाओं, युवाओं और काश्तकारों की ऋण जरुरतों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र बनाया जायेगा।

श्री मीणा जयपुर जिले की आमेर पंचायत समिति के जालसू गॉव में जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के विस्तार पटल के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। मंत्री महोदय ने जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक की ओर से 9 काश्तकारों को 9 लाख 50 हजार एवं जयपुर पीएलडीबी की ओर से डेयरी के लिए 5 ऋणियों को 5 लाख 50 हजार रु. के ऋण के चैक दिए। आरंभ में शिलापट्टिका का अनावरण एवं फीता काटकर बैंक के विस्तार पटल का विधिवत् शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने के साथ ही संचालक मण्डल को अधिक अधिकार संपन्न बनाया है। अब ऋण स्वीकृति के सारे अधिकार संचालक मण्डल को दे दिए गए हैं। संचालक मण्डल के सदस्यों को जाँच परख कर ऋण स्वीकृत करने होंगे, यदि बोगस या दिए गए ऋणों की वसूली नहीं होती है तो इसके लिए संचालक मण्डल के सदस्यों की जिम्मेदारी तय होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 लाख नए किसानों सहित 21 लाख किसानों को 5 हजार करोड़ के फसली ऋण देने का निर्णय किया है, ब्याज दर में कटौती के साथ ही समय पर ऋण चुकाने वालों को दो प्रतिशत की छूट देते हुए पांच प्रतिशत पर ऋण देना तय किया है। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों को पैसा किसानों का पैसा है और अब बोगस या गलत ऋण वितरण को किसी भी हालत में सहन नहीं किया जायेगा।

श्री मीणा ने कहा कि राज्य सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन का निर्णय करते हुए हिस्सा राशि को भी 15 लाख से घटाकर 7 लाख रुपए कर दी है। इसी तरह से तहसील स्तर पर 40 नई क्रय–विक्रय और आदिवासी इलाकों में 100 नई लेम्प्स खोलने जा रही है। पहलीबार किसानों को सस्ती दर पर ऋण देने के लिए राज्य सरकार 30 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। सरकार का प्रयास है कि काश्तकारों व आम नागरिकों को उनके नजदीक से बेहतर सहकारी सेवाएं प्राप्त हो। सरकार ने नियत समय पर चुनाव कराने का निर्णय कर लिया अब चुने हुए संचालकों का भी दायित्व हो जाता है कि वे राज्य के सहकारी आंदोलन को महाराष्ट्र व गुजरात जैसा अग्रणी सहकारी आंदोलन बनाने में भागीदारी निभाएं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बाबू लाल नागर ने कहा कि अब पूरे प्रदेश में सस्ती दर पर आटा, दाल, चावल, सोया तेल, मटर दाल उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चाकचोबंद करते हुए सभी 23 हजार राशन की दुकानों पर प्रतिमाह 15 से 21 तरीख तक उपभोक्ता सामग्री के वितरण की देखरेख के लिए 23 हजार सरकारी कर्मचारियों को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध का जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। 36 लाख 57 हजार राज्य बीपीएल और एपीएल परिवारों को 2 रुपए किलो गेहूँ आदि उपलब्ध कराया जा रहा है।

जयपुर सीसीबी के अध्यक्ष श्री भंवर लाल जादू ने जयपुर जिले में हर तहसील में बैंक शाखा खोलने की मंशा जताई। जयपुर भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष श्री लादू राम चौधरी ने किसानों से दीर्घकालीन कृषि सुधार कार्यों के लिए भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने का आग्रह किया। जयपुर के जिला प्रमुख श्री हजारी लाल नागर ने आमनागरिकों से एक–एक पौधरोपण का आग्रह करते हुए परिवार के सदस्य की तरह पौधे का पालन करने को कहा।

जयपुर सीसीबी के प्रबन्ध संचालक श्री विष्णु कुमार वर्मा ने बैंक 4 करोड़ 86 लाख के लाभ में काम कर रहा है। इस साल जिले के 25 हजार नए काश्तकारों सहित 200 करोड़ के फसली सहकारी ऋण दिए जायेंगे। जालसू ग्राम पंचायत के सरपंच श्री रमेश यादव ने जालसू में बैंक शाखा खोलने पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संयुक्त रजिस्ट्रार जयपुर खण्ड श्री सीताराम मीणा, जयपुर पीएलडीबी सचिव श्री मदन लाल गुर्जर, सहायक रजिस्ट्रार ग्रामीण श्री राजेन्द्र मीणा सहित सहकारी अधिकारी, जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में काश्तकार व महिलाएं उपस्थित थे। संचालन श्री एस.के. शर्मा ने किया।

स्वामी, रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी, राजस्थान, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री मुकेश शर्मा द्वारा नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम, भवानी सिंह रोड, जयपुर से प्रकाशित एवं मैसर्स राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड़, जी-1/138, इंडस्ट्रियल एरिया मालवीय नगर, जयपुर से मुद्रित ● संपादक : डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा।